न्यायाधीश *सुवीर सहगल* के समक्ष

रंजीत @ अंगरेजी @ बिट्टू—*याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2020 का सीआरआर नंबर 656

अगस्त 13, 2020

स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, धारा 21 (बी), 36-ए, 61 और 85-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 167 (2) - चूक जमानत - अधिकार की जब्ती, जब- धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट के साथ नहीं - अधूरा चालान दायर किया गया - याचिकाकर्ता ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया - नोटिस पर राज्य ने एफएसएल रिपोर्ट दायर की - सत्र न्यायाधीश द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन को दो जमानतों के साथ जमानत बांड प्रस्तुत करने पर अनुमति दी गई थी - याचिकाकर्ता इसे प्रस्तुत कर सकता था केवल बाद में दिन में, न्यायालय के घंटों के बाद, एक आवेदन दायर करके, जिसे यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि अदालत के घंटों तक जमानत बांड प्रस्तुत न करने पर डिफ़ॉल्ट जमानत का उसका अधिकार जब्त हो गया था - यह माना जाता है, संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत अव्यवहार्य अधिकार है, जो एफएसएल रिपोर्ट दायर करके आरोप पत्र में दोष को दूर करने से पराजित नहीं होता है - आगे कहा गया, संहिता में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता को जमानत आदेश की प्रत्याशा में जमानत बांड और ज़मानत के साथ तैयार रहना होगा- जमानत देने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए अभियुक्त को एक उचित अवसर दिए जाने की आवश्यकता है- और उचित अवसर मामले से मामले में अलग-अलग होंगे- आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को जमानत बांड और ज़मानत प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया।

माना जाता है कि उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में जांच किए जाने पर वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि हालांकि चालान 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, जैसा कि संहिता की धारा 167 (2) के साथ पठित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए के तहत प्रदान किया गया था, लेकिन यह अधूरा था क्योंकि यह रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के साथ नहीं था। याचिकाकर्ता ने उपाय का लाभ उठाया और संहिता की धारा 167 (2) को लागू करके जमानत मांगी, जिसे 10.02.2020 को ***रविंदर @ बाइंडर*** बनाम ***हरियाणा राज्य*** 2015 (4) आरसीआर (सीआरएल) 441 में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करके अनुमति दी गई थी, और तदनुसार आरोपी-याचिकाकर्ता को "डिफ़ॉल्ट जमानत" दी गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आरोपी-याचिकाकर्ता ने निर्धारित अवधि समाप्त होने पर उसे उपलब्ध अधिकार का प्रयोग किया था और उस पर सत्र न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था। तथ्य यह है कि एफएसएल रिपोर्ट उनके आवेदन के निर्णय से पहले दायर की गई थी, संहिता की धारा 167 (2) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार को पराजित नहीं करता है, खासकर जब रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि राज्य ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। संहिता की धारा 167 (2) के तहत

जमानत का अधिकार अपरिहार्य अधिकार होने के कारण, केवल इसलिए पराजित नहीं हो जाता क्योंकि आरोप पत्र में दोष एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करके दूर किया गया था और वह भी निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद।

(पैरा 10)

आगे आयोजित, जो राज्य के वकील के दूसरे तर्क पर आ रहा है कि याचिकाकर्ता को जमानत आदेश पारित होने पर अपेक्षित जमानत बांड और ज़मानत के साथ तैयार और तैयार रहने की आवश्यकता थी। संहिता में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आरोपी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अनुकूल आदेश की प्रत्याशा में जमानत बांड और जमानतदार के साथ तैयार रहेगा। जमानत देने का आदेश पारित होने पर, जमानत देने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए अभियुक्त को एक उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित अवसर के लिए क्या राशि हो सकती है, यह मामले से मामले में भिन्न होगा। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां अभियुक्त उस स्थान, राज्य या क्षेत्र से संबंधित नहीं है जहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जमानत की शर्तों को तुरंत पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इस तरह के कारण को उसके संज्ञान में लाए जाने पर, न्यायालय अभियुक्त को आवश्यक कदम उठाने के लिए पर्याप्त लंबा समय दे सकता है। आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित होने के तुरंत बाद आरोपी को जमानत बांड और जमानतदार भरने की आवश्यकता नहीं है। एक हाथ से जमानत देना और दूसरे हाथ से इस आधार पर इनकार करना कि आरोपी ने जमानत देने की शर्तों को तुरंत पूरा नहीं किया, न्याय का उपहास है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के वकील अमित चौधरी।

राजीव गोयल, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी-राज्य के लिए।

सुवीर सहगल जे.

(एक) कोविड-19 महामारी के कारण अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाया गया है।

(दो) याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद द्वारा पारित दिनांक 10.02.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है।

(तीन) संक्षेप में तथ्य यह है कि एफआईआर नंबर 579 दिनांक 07.11.2019 को एन**आर्कोटिक ड्रग्स** एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षिप्तता के लिए "एनडीपीएस अधिनियम") की धारा 21 (बी) / 61/85 के तहत पुलिस स्टेशन फतेहाबाद में दर्ज किया गया था, इस आरोप पर कि आरोपी-याचिकाकर्ता को कुछ प्रतिबंधित के साथ पकड़ा गया था। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह हिरासत में है। दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट 06.01.2020 को विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट के साथ यह नहीं थी। चूंकि पुलिस द्वारा अधूरा चालान दायर किया गया था और इसे दाखिल करने की अपेक्षित अवधि समाप्त हो गई थी, याचिकाकर्ता ने 07.02.2020 को संहिता की धारा 167 (2) के साथ पठित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए के तहत जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया। नोटिस पर, राज्य ने जवाब दायर किया। दिनांक 10.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय में एफएसएल रिपोर्ट दायर की

गई, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के पास से बरामद मादक पदार्थ 10 ग्राम हेरोइन साबित हुआ। आवेदन पर विचार करने के बाद, सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 10.02.2020 के आदेश के तहत आवेदन को अनुमति दी और याचिकाकर्ता को अदालत की संतुष्टि के लिए दो जमानतों के साथ 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी। न्यायालय ने इसके साथ ही कहा कि अपेक्षित जमानत बांड और जमानतदार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। दिन के उत्तरार्ध के दौरान, याचिकाकर्ता ने जमानत और ज़मानत बांड की स्वीकृति और सत्यापन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करके खारिज कर दिया: -

> "मामले की फाइल शाम 4.40 बजे याचिकाकर्ता/आरोपी रंजीत @ अंगरेजी @ बिट्टू की ओर से इस आधार पर जमानत और ज़मानत बांड की स्वीकृति और सत्यापन के लिए एक आवेदन के रूप में फिर से ली गई कि याचिकाकर्ता/आरोपी रंजीत @ अंगरेजी @ बिट्टू को आज यानी 10.02.2020 को इस अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है।
>
> सुना। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ता/आरोपी रंजीत @ अंगरेजी @ बिट्टू को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए और सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत आज सुबह इस अदालत द्वारा जमानत दी गई। हालांकि, याचिकाकर्ता/आरोपी रंजीत @ अंगरेजी @ बिट्टू की ओर से अदालत के घंटों यानी शाम 4.30 बजे तक अपेक्षित जमानत और ज़मानत बांड प्रस्तुत नहीं किए गए थे और जमानत बांड की स्वीकृति और सत्यापन के लिए वर्तमान आवेदन लगभग 4.40 बजे दायर किया गया है। **याचिकाकर्ता/अभियुक्त को उसे डिफ़ॉल्ट जमानत देने पर तैयार रहना और जमानत बांड प्रस्तुत करना था, लेकिन वह अदालत के घंटों तक अपेक्षित जमानत बांड प्रस्तुत करने में विफल रहा। आज न्यायालय के घंटों तक अपेक्षित जमानत बांड प्रस्तुत न करने पर याचिकाकर्ता/अभियुक्त की डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार जब्त कर लिया गया है।** इसके अलावा, जमानतदारों में से एक मजबूत नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भूमि संपत्ति नहीं है और उसने केवल मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति रखी है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जमानत और ज़मानत बांड स्वीकार नहीं किए जाते हैं और जमानत और ज़मानत बांड की स्वीकृति और सत्यापन के लिए वर्तमान आवेदन खारिज कर दिया जाता है। कागजात को मुख्य मामले की फाइल के भीतर टैग किया जाए।

(चार) याचिकाकर्ता के खिलाफ पीड़ित ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(पाँच) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत एक अपरिहार्य अधिकार है और एक बार दिए जाने के बाद, इसे केवल इसलिए जब्त नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता आदेश पारित होने के समय या आदेश पारित होने के दिन के दौरान ज़मानत और जमानत बांड प्रस्तुत नहीं कर सका। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था।

(छः) राज्य के वकील ने दो आधारों पर पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया है। सबसे पहले, उनका निवेदन यह है कि चूंकि केमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, इसलिए चालान को अधूरा नहीं

कहा जा सकता था और इसलिए, डिफ़ॉल्ट जमानत देने का अवसर अब नहीं बचा है। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया है कि जमानत आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में विफल रहने के कारण, याचिकाकर्ता उसी से संतुष्ट होने के लिए एक और अवसर का हकदार नहीं था। कस्टडी सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 12 अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें से 04 मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत हैं और वह 02 मामलों में दोषी हैं।

(सात) मैंने पार्टियों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

(आठ) राज्य के वकील का पहला तर्क ध्यान देने योग्य है और खारिज कर दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***रघुबीर सिंह और अन्य*** *बनाम* ***बिहार राज्य***[1] (पैरा 22) में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

> "22. हमारी चर्चा और इसमें केस-लॉ का परिणाम: धारा 167 (2) के परंतुक के तहत की गई जमानत पर रिहाई का आदेश समय की चुप्पी, आरोप पत्र दाखिल करने या धारा 309 (2) के तहत हिरासत में रिमांड द्वारा पराजित नहीं होता है। हालांकि जमानत पर रिहाई के आदेश को धारा 437 (5) या धारा 439 (2) के तहत रद्द किया जा सकता है। आम तौर पर जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर, हस्तक्षेप या न्याय के प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का प्रयास, या न्याय के पाठ्यक्रम से बचने का प्रयास, या उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। गवाहों को डराकर या धमकाकर, जांच में हस्तक्षेप करके, सबूतों को बनाने या गायब करने आदि के द्वारा न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्याय के पाठ्यक्रम को देश छोड़ने या भूमिगत होने या अन्यथा खुद को जमानतदारों की पहुंच से परे रखकर टालने या टालने का प्रयास किया जा सकता है। वह इसी तरह के या अन्य गैरकानूनी कृत्यों में लिप्त होकर उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। जहां धारा 167(2) के परंतुक के तहत साठ दिनों में जांच पूरी न करने में अभियोजन की चूक के लिए जमानत दी गई है, आरोप पत्र दाखिल करने से दोष दूर होने के बाद, अभियोजन पक्ष इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ने गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और प्रतिबद्ध करना आवश्यक है उसे हिरासत में ले लिया गया। अंतिम उल्लेखित मामले में, वास्तव में बहुत मजबूत आधार की उम्मीद की जाएगी।

(नौ) उदय मोहनलाल आचार्य ***बनाम*** *महाराष्ट्र राज्य* ***(पैरा 13)*** [2] **में,** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: -

> "दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 167 की उपधारा (2) के परंतुक में इंगित अवधि की समाप्ति के बाद हिरासत में किसी अभियुक्त को हिरासत में रखने को अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है, सिवाय स्पष्टीकरण I में इंगित आकस्मिकता के, अर्थात्, यदि अभियुक्त जमानत प्रस्तुत नहीं करता है। यह इस अर्थ में कहा जा सकता है कि यदि अवधि समाप्त होने के बाद, जमानत पर

[1] 1986 (4) एससीसी 481

[2] 2001 (5) एससीसी 453

रिहा होने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है, और अभियुक्त जमानत प्रस्तुत करने की पेशकश करता है, और इस तरह अपने अपरिहार्य अधिकार का लाभ उठाता है और फिर कुछ नियमों और शर्तों पर जमानत का आदेश पारित किया जाता है लेकिन अभियुक्त जमानत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, और उस समय चालान दायर किया जाता है तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि आरोपी का अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन जब तक अभियुक्त एक आवेदन दायर करता है और न्यायालय के उचित आदेशों द्वारा रिहा होने पर जमानत की पेशकश करने के लिए आवेदन में इंगित करता है, तब तक जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के अधिकार को मजिस्ट्रेट के उपलब्ध नहीं होने और मामले को स्थानांतरित नहीं किए जाने की संभावना पर निराश नहीं किया जा सकता है, या कि मजिस्ट्रेट गलती से आदेश पारित करने से इनकार कर देता है और मामले को उच्च मंच पर ले जाया जाता है और इंटररेग्नम में चालान दायर किया जाता है।

(दस) उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में जांच किए जाने पर वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि हालांकि चालान 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, जैसा कि संहिता की धारा 167 (2) के साथ पठित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए के तहत प्रदान किया गया था, लेकिन यह अधूरा था क्योंकि यह रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के साथ नहीं था। याचिकाकर्ता ने उपाय का लाभ उठाया और संहिता की धारा 167 (2) को लागू करके जमानत मांगी, जिसे 10.02.2020 को ***रविंदर @ बाइंडर*** बनाम ***हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करके अनुमति दी गई थी***[3]**,** और तदनुसार आरोपी-याचिकाकर्ता को "डिफ़ॉल्ट जमानत" दी गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आरोपी-याचिकाकर्ता ने निर्धारित अवधि समाप्त होने पर उसे उपलब्ध अधिकार का प्रयोग किया था और उस पर सत्र न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था। तथ्य यह है कि एफएसएल रिपोर्ट उनके आवेदन के निर्णय से पहले दायर की गई थी, संहिता की धारा 167 (2) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार को पराजित नहीं करता है, खासकर जब रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि राज्य ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत का अधिकार अपरिहार्य अधिकार होने के कारण, केवल इसलिए पराजित नहीं हो जाता क्योंकि आरोप पत्र में दोष एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करके दूर किया गया था और वह भी निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद।

(ग्यारह) राज्य के वकील के दूसरे तर्क पर आते हुए कि याचिकाकर्ता को जमानत आदेश पारित होने पर अपेक्षित जमानत बांड और ज़मानत के साथ तैयार और तैयार रहने की आवश्यकता थी। संहिता में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आरोपी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अनुकूल आदेश की प्रत्याशा में जमानत बांड और जमानतदार के साथ तैयार रहेगा। जमानत देने का आदेश पारित होने पर, जमानत देने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए अभियुक्त को एक उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित अवसर के लिए क्या राशि हो सकती है, यह मामले से मामले में भिन्न होगा। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां अभियुक्त उस स्थान, राज्य या क्षेत्र से संबंधित नहीं है जहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जमानत की शर्तों को तुरंत पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इस तरह के कारण को उसके संज्ञान में लाए जाने पर, न्यायालय अभियुक्त को आवश्यक कदम उठाने के लिए

[3] 2015 (4) आरसीआर (सीआरएल) 441

पर्याप्त लंबा समय दे सकता है। आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित होने के तुरंत बाद आरोपी को जमानत बांड और जमानतदार भरने की आवश्यकता नहीं है। एक हाथ से जमानत देना और दूसरे हाथ से इस आधार पर इनकार करना कि आरोपी ने जमानत देने की शर्तों को तुरंत पूरा नहीं किया, न्याय का उपहास है।

(बारह) वर्तमान मामले में, आरोपी ने उसी दिन जमानत बांड और जमानत स्वीकार करने के लिए अदालत के घंटों के बाद एक आवेदन दायर किया है। चूंकि न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ज़मानत से संतुष्ट नहीं था, इसलिए अदालत को उसे ज़मानत प्रस्तुत करने का एक और अवसर देने की आवश्यकता थी, बजाय इसके कि डिफ़ॉल्ट जमानत जब्त हो गई। इसलिए, आक्षेपित आदेश को इस सीमा तक कायम नहीं रखा जा सकता है।

(तेरह) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, अभियुक्त-याचिकाकर्ता के आवेदन पर पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.02.2020 को सत्र न्यायालय ने कहा कि "*याचिकाकर्ता/अभियुक्त को तैयार रहने और उसे डिफ़ॉल्ट जमानत देने पर जमानत बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह अदालत के घंटों तक आवश्यक जमानत बांड प्रस्तुत करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता/अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को आज अदालत के घंटों तक अपेक्षित जमानत बांड प्रस्तुत न करने पर जब्त कर लिया गया है*" को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए अपेक्षित जमानत बांड और जमानत प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाता है।

(चौदह) तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका का निपटान किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

अंबाला, हरियाणा